



- श्री हरगोबिन्दर सिंह धालीवाल ने कल अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है।
- अण्डमान निकोबार जी एस टी आयुक्त अर्जुन शर्मा ने जाली जी एस टी पंजीकरण के पच्चीस मामलों को रद्द कर दिया है।
- दक्षिण अण्डमान ज़िले की वार्षिक सम्मरी रिविज़न के लिए गतिविधियां आरंभ की गई है।
- दक्षिण अण्डमान जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
- अण्डमान निकोबार चेस एसोसिएशन की ओर से उन्नीस वर्ष आयुवर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए आयोजित चेस चैम्पियनशिप का समापन हो गया है।



श्री हरगोबिन्दर सिंह धालीवाल ने कल अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। आज सुबह साढ़े आठ बजे पुलिस लाईन परेड मैदान में इनके सम्मान में रस्मी परेड का आयोजन किया जाएगा।



पुलिस की मदक विरोधी पुलिस थाना टीम ने पांच सौ चालीस ग्राम गांजा ज़ब्त करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी प्रीतम बिहारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मिताली हलदार नामक पच्चीस वर्षीय एक महिला को गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया।



अण्डमान निकोबार जी एस टी आयुक्त अर्जुन शर्मा ने जाली जी एस टी पंजीकरण के पच्चीस मामलों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा बचे बीस अन्य कराए गए पंजीकरण यू टी जी एस टी आयुक्त के परिधि से बाहर है और इसे भी रद्द किया जाएगा। यू टी जी एस टी अधिकारियों

की ओर से मायाबंदर में जाली दस्तावेजों की सहायता से संभावित जी एस टी पंजीकरण का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों के परिसर में पहुंचने पर यह पता लगा कि जी एस टी पंजीकरण में दिया गया पता अस्तित्व में नहीं है और यह पंजीकरण सिर्फ अवैध रूप से आई टी सी पास कराने के उद्देश्य से किया गया था। निरीक्षण के दौरान नौ पैन नम्बरों से पैंतालीस जी एस टी पंजीकरण की पहचान हुई। श्री अर्जुन शर्मा ने कहा कि इस वर्ष मई से अब तक जाली आई टी सी में करीब दो करोड़ रुपये का पता लगा है। इस मामले में मुख्य आरोपी और द्वीपों में संचालित ऐसे गिरोह की पहचान के लिए काम किया जा रहा है। पैन नम्बरों के खिलाफ एफ आई आर पहले ही दर्ज की जा चुकी है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।



दक्षिण अंडमान ज़िले की वार्षिक सम्मरी रिविज़न के लिए गतिविधियां आरंभ की गई हैं। इसका उद्देश्य सटीक और भरोसेमंद मतदाता सूची को तैयार करना है। री-रिविजनकरण के तहत बूथ स्तर के अधिकारी मतदाताओं के वर्तमान क्षेत्र में मतदाता सूची में उनके नामों की घर-घर जाकर जांच करेंगे और परिवारों के मुखिया से जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा ये अधिकारी अगले वर्ष एक जनवरी तक भावी मतदाताओं के अलावा अगले वर्ष एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर तक मतदान के योग्य होने वाले भावी मतदाताओं के बारे में भी सूचना एकत्र करेंगे। इसके अलावा मतदाता सूची में प्रविष्टियों में जरूरी सुधार का कार्य भी किया जाएगा। इस वर्ष उनतीस अक्टूबर को एकीकृत मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। उनतीस अक्टूबर से अट्ठाईस नवम्बर के बीच दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और अगले वर्ष छः जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। ज़िला प्रशासन ने इस प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों को सहयोग देने का अनुरोध किया है। मतदाता अपने मोबाइल नम्बर और आधार को भी लिंक कराने के लिए जानकारी दे सकते हैं।



सरकार ने वित्त मंत्रालय से छियालीस हजार से अधिक रुपये की वित्तीय सहायता देने की दावेदारी करने वाले लिंक को फर्जी बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फैक्ट चेक इकाई ने फर्जी समाचार का भंडाफोड़ किया है। संदेश प्राप्त करने वालों को गुमराह कर एक फर्जी लिंक के जरिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने को कहा गया।



दक्षिण अण्डमान जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। स्वराजद्वीप में चलाए गए अभियान में करीब चार हैक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। इसके अलावा विम्बर्लीगंज में सरकारी ज़मीन पर बने एक अस्थायी ढांचे को भी हटाया गया।

उधर, जिला प्रशासन ने बिड़नाबाद गांव में एक पेय जल कुएं और एक बोरवेल को सील किया है। केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण पूर्वी क्षेत्र कोलकाता की ओर से दिए गए चेतावनी के बाद यह कार्रवाई की गई है, ताकि दूषित जल स्रोतों का इस्तेमाल न किया जा सके।



मुख्यभूमि के विभिन्न संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वीपों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित अनुपयोगी सीटों का आवंटन कल सुबह दस बजे से टैगोर कॉलेज के सभागार में किया जाएगा। इनमें बी.एफ.एस.सी., बी एस सी बागवानी, सामान्य नर्सिंग, बी.एड भोपाल की दो-दो सीट, जबकि बी. टेक फिशरीज़ इंजीनियरिंग और मलयाली मूल के लिए बी एस सी कृषि की एक-एक सीट शामिल हैं।

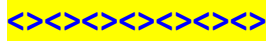
उधर, अंडमान कॉलेज में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुछ सीटें रिक्त हैं। अंतिम योग्यता सूची में शामिल उम्मीदवारों से उनतीस अगस्त को सुबह साढ़े नौ बजे परामर्श के लिए उपस्थित रहने को कहा गया है।

इस बीच, अंडमान कॉलेज में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए प्रथम वर्ष की कक्षाएं आज से आरंभ होगी।



मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन आई सी डी एस परियोजना ग्रामीण-डिगलीपुर के सहयोग से कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन ने बच्चों को कुपोषणमुक्त बनाने और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कुपोषित मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत हाल ही में सीतानगर ग्राम पंचायत के कृष्णापुरी गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, पोषण दो दशमलव शून्य के खंड समन्वयक ने पांच साल से छोटे बच्चों में पोषण और पूरक आहार पर जोर दिया। कार्यक्रम में आई सी डी एस के अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य और क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित थे।



तीस अगस्त को पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता जाने वाले जलयान एम. वी स्वराजद्वीप के यात्रा कार्यक्रम में फेर-बदल किया गया है। अब ये जलयान तीस अगस्त के स्थान पर कल शाम चार बजे पोर्ट ब्लेयर से छूटेगा। जिन यात्रियों ने तीस अगस्त की यात्रा के लिए टिकट खरीदे हैं, वे अब उसी टिकट पर यात्रा कर सकते हैं।



अण्डमान निकोबार चेस एसोसिएशन की ओर से उन्नीस वर्ष आयुवर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए आयोजित चेस चैम्पियनशिप का समापन हो गया है। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित इस चैम्पियनशिप में एम. ए. दिनाकर को विजेता और युवान सिंह को उप-विजेता घोषित किया गया। लड़कियों की श्रेणी में वाई रिनी रोसलिन को पहला और परनिता को दूसरा स्थान मिला। समापन अवसर पर अबर्डीन थाना प्रभारी विशाल राम मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दोनों श्रेणियों के सर्वश्रेष्ठ पन्द्रह खिलाड़ियों में पुरस्कार बांटे।



विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई जैव-आर्थिक नीति से आगामी वर्षों में भारत विश्व में अग्रणी देश होगा। डॉ सिंह ने नई दिल्ली में जैव-आर्थिक नीति की जानकारी देते हुए कहा कि देश की जैव-अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह दो हजार चौदह की दस अरब डॉलर से बढ़कर दो हजार चौबीस में एक सौ तीस अरब डॉलर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा स्रोत के हानि जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नई जैव आर्थिक नीति तैयार की गई है।

